International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

वसीयतनामा उत्तराधिकार पर हिंदू कानून का एक अध्ययन

VISHWA MOHAN MISHRA
RESEARCH SCHOLAR DEPARTMENT OF LAW OPJS UNIVERSIty, CHURU, RAJASTHAN

DR. RAVI TYAGI
PROFESSOR DEPARTMENT OF LAW OPJS UNIVERSITY, CHURU, RAJASTHAN

सारांश

इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न भारतीय धर्मों के बीच वसीयतनामा उत्तराधिकार के संबंध में ऊपर किया गया है। वसीयती उत्तराधिकार की शुरुआत से लेकर आज तक विभिन्न संप्रदायों, नियमों और प्रथागत कानूनों पर बेहतर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसलिए, वसीयतनामा उत्तराधिकार का आधार, निष्पादन और विधि अब संक्षेप में निष्कर्ष निकाला जा रहा है। 1865 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पहले भारत में नियंत्रित था। यह अधिनियम मुख्य रूप से अंग्रेजी कानूनों पर आधारित था और कुछ अपवादों के अधीन, सभी प्रकार की वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार के लिए प्रभावी नियम था। हालाँकि, अपवाद इतने व्यापक थे कि सभी भारतीयों को छूट थी। हिंदू वसीयत अधिनियम भी 1870 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की सभी धाराएँ सभी हिंदुओं की वसीयतों और संहिताओं तक फैली हुई हैं। 1881 में यह अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम को हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमानों पर भी लागू किया गया। अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पहले के 1865 अधिनियम, हिंदू विल अधिनियम, भारतीयों की परिवीक्षा पर अधिनियम और प्रशासन पर अधिनियम और यहां तक कि भारतीयों के उत्तराधिकार पर अधिनियम को समेकित करता है। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि निर्वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार कानून को संशोधित किया जाना है। यह अंग्रेजी कानून के कोड को काफी हद तक समाहित करता है। जहां तक उन चीजों का सवाल है जो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को हिंदू

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में उनके व्यक्तिगत कानून द्वारा विनियमित किया जाता है। "नियम" शब्द किसी भी प्रक्रियात्मक कानून, इलेक्ट्रॉनिक कानून या सीमा शुल्क कानून का गठन करेगा।

मुख्यशब्द: हिंदू कानून, उत्तराधिकार, वसीयतनामा, समेकित

प्रस्तावना

भारत में उत्तराधिकार को पहले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 द्वारा विनियमित किया गया था। यह अधिनियम मुख्य रूप से अंग्रेजी कानूनों पर आधारित था, और कुछ अपवादों के अधीन, ब्रिटिश भारत में लागू कानून का गठन किया गया था, जो वसीयतनामा और निर्वसीयत उत्तराधिकार के सभी वर्गों पर लागू था। हालाँकि, अपवाद इतने व्यापक थे कि भारत के सभी मूल निवासियों को इसके अंतर्गत बाहर रखा गया था। अतः, 1870 में, हिंदू विल्स अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के कुछ अंश हिंदुओं द्वारा की गई सभी वसीयतों और संहिताओं पर भी लागू होंगे। बाद में 1881 में प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट को हिंदू और मुस्लिम दोनों पर लागू किया गया। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, 1865 के पहले अधिनियम, हिंदू वसीयत अधिनियम, प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम और पारसी निर्वसीयत उत्तराधिकार अधिनियम को समेकित करता है। अधिनियम की प्रस्तावना इंगित करती है कि अधिनियम का उद्देश्य निर्वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार पर लागू कानून को समेकित करना है। यह काफी हद तक अंग्रेजी कानून के नियम का प्रतीक है। जहां तक उन मामलों का संबंध है जो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, हिंदू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होते हैं और मुस्लिम अपने व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित होते हैं। अधिकांश भारतीय जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, वसीयत के मामले में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित होते हैं, जो उनके व्यक्तिगत कानून की रक्षा करने वाले कुछ विशेष प्रावधानों के अधीन होते हैं। इन विशेष प्रावधानों को अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में ही शामिल कर दिया गया है। इसलिए वसीयत के हिंदू कानून को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में निर्धारित वसीयत उत्तराधिकार के कानून के तहत पाया और अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारी चर्चा तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि वसीयतनामा उत्तराधिकार के इतिहास का संक्षिप्त संदर्भ न दिया जाए। जहां तक हिंदू कानून का सवाल है, हिंदुओं के बीच वसीयतनामा शक्ति की उत्पत्ति और वृद्धि अस्पष्टता से भरी है। विल का विचार धर्मशास्त्रों के लेखकों और उन टिप्पणीकारों के लिए पूरी तरह से अज्ञात था जिनके काम ने हिंदू कानून के विभिन्न विद्यालयों को जन्म दिया। पुरानी हिंदू संयुक्त परिवार

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

प्रणाली को संपत्ति पर प्रभुत्व की किसी भी अवधारणा के साथ असंगत माना जाता था और शायद यही कारण था कि ब्रिटिश भारत में स्थापित अदालतों द्वारा हिंदू की वसीयती शक्ति के किसी भी प्रश्न को मान्यता नहीं दी गई थी।1 शुरुआती समय में पारिवारिक संपत्ति परिवार में निहित था और परिवार के सदस्यों को केवल भोग का अधिकार था।

ऐसी स्थिति होने पर कोई भी व्यक्तिगत सदस्य वसीयत द्वारा संपत्ति के निपटान के विचार की कल्पना नहीं कर सकता है जो निष्पादक की मृत्यु के बाद प्रभावी होगा। लेकिन हिंदू कानून के ऐसे पाठ हैं जिनमें वसीयत के वास्तविक अंकुर शामिल हैं, और जो वसीयतनामा स्वभाव को विनियमित करने वाले एक पूर्ण कानून के रूप में विकसित हो सकते थे। हालांकि, इन ग्रंथों का वसीयतनामा शक्ति के अभ्यास के लिए लाभ नहीं उठाया गया था। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ही हिंदुओं ने वसीयत बनाने के बारे में सोचा। हिंदुओं द्वारा बनाई गई वसीयत को उच्च न्यायालयों से जुड़े अंग्रेजी वकीलों द्वारा न्यायाधीश, वकील और सॉलिसिटर के रूप में मान्यता दी जाने लगी। वसीयत बनाने का विचार हिंदुओं में सहज विकास का था। कलकत्ता और अन्य प्रेसीडेंसी-नगरों के अमीर हिंदुओं के पास कानूनी सलाह के लिए अंग्रेज वकील थे, जिन्होंने उन अमीर हिंदुओं के लिए वसीयत तैयार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार हिंदुओं ने अंग्रेजी सॉलिसिटरों और पहले से संदर्भित विधायी अधिनियम से वसीयतनामा स्वभाव के विचार को आत्मसात किया। यह विचार धीरे-धीरे प्रेसीडेंसी-नगरों के बाहर के क्षेत्रों और जमींदारों के अलावा अन्य व्यक्तियों तक फैल गया।

उत्तराधिकार

उत्तराधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसमें निहित संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तांतरण है। सभी देशों में, उत्तराधिकार कानून द्वारा विनियमित होता है। हालाँकि, कानूनी इतिहासकारों ने पाया है कि विभिन्न देशों में उत्तराधिकार के ऐसे कानूनों की कोई सार्वभौमिक रूप से समान उत्पत्ति नहीं है; वे पूरी दुनिया में एक समान तरीके से विकसित नहीं हुए हैं। ऐसी प्रणालियाँ हैं जिनमें उत्तराधिकार के कानून के विकास में धर्म ने प्रमुख भूमिका निभाई है। हिंदू समुदाय उस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण है। प्राचीन हिंदू कानून-निर्माता, मनु ने कहा: "तीन बार जल अवश्य देना चाहिए; तीन को पिंड अवश्य देना चाहिए, चौथा दाता है। एक सपिंड की संपत्ति निकटतम सपिंड को जाती है," जिससे आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने के कर्तव्य और एक मृत हिंदू की संपत्ति लेने के अधिकार के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रदर्शन होता है। हिंदुओं का मानना था कि विरासत और उत्तराधिकार का हिंदू कानून दैवीय अध्यादेश पर स्थापित किया गया था। उत्तराधिकार में उत्तरजीविता2 शामिल नहीं है। उत्तराधिकार का अर्थ केवल उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण है न कि वसीयत के तहत वसीयत द्वारा।3। फिर से ऐसे समुदाय हैं जिनमें पारिवारिक अधिकार और सामुदायिक स्वामित्व की प्रणालियाँ

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

प्रचलित थीं, जिन्हें धीरे-धीरे व्यक्तिगत स्वामित्व के रूपों ने प्रतिस्थापित कर दिया है। इन समुदायों के संबंध में, प्रोफेसर प्लकेट ने उत्तराधिकार के कानून को "संपत्ति के संदर्भ में परिवार को व्यक्त करने का प्रयास" कहा है।

उत्तराधिकार के प्रकार

उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून केवल क्रमिक वृद्धि का है। विवाद उत्पन्न होने तक उत्तराधिकार के कानून की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कानून विकसित हो गया है और वर्तमान समय में उत्तराधिकार के कानून से हमारा तात्पर्य उस कानून से है जो मृत्यु के बाद एक व्यक्ति की संपत्ति को एक या अधिक व्यक्तियों को हस्तांतरित करने को नियंत्रित करता है। आधुनिक समय में उत्तराधिकार के कानून को वसीयतनामा उत्तराधिकार के कानून और निर्वसीयत उत्तराधिकार के कानून में विभाजित किया गया है। वसीयतनामा उत्तराधिकार का कानून उस व्यक्ति की संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है जो वसीयत करके इसका निपटान करते हुए मर जाता है। दूसरी ओर, राज्य उत्तराधिकार का कानून, एक मृत व्यक्ति की अविवादित संपत्ति के हस्तांतरण और वितरण को नियंत्रित करता है। प्रारंभिक समुदायों में एक वसीयत बाद के कानून में जो बन गई उससे बहुत अलग थी। यह सामान्यतः आसन्न मृत्यु के सन्देश के रूप में था। तदनुसार, आम तौर पर इसका सहारा तब लिया जाता था जब एक वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार सामान्य तरीके के विपरीत वितरित करना चाहता था जिसमें संपत्ति प्रचलित प्रथागत कानून के आधार पर पारित होती। डायवर्ट करने की यह शक्ति किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपूर्ण संपत्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आम तौर पर संपत्ति के एक अंश तक ही सीमित थी। विरासत का एक निश्चित अनुपात हमेशा विधवा और बच्चों जैसे करीबी संबंधों को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके निशान अभी भी वसीयत से संबंधित कई आधुनिक कानूनों में पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में, मृतक के ये आश्रित कम से कम तीसरे पक्ष को दी गई संपत्ति से अपने भरण-पोषण के प्रावधान का दावा कर सकते हैं।

वसीयतनामा उत्तराधिकार की आवश्यकता

"प्रत्येक सभ्य लोगों का कानून संपत्ति के मालिक को अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार, पूर्ण या आंशिक रूप से यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि जो प्रभाव वह अपने पीछे छोड़ता है, वह किस पर पारित होगा। फिर भी यह स्पष्ट है कि, यद्यपि कानून संपत्ति के मालिक को इस अंतिम निपटान में पूर्ण स्वतंत्रता देता है जिसमें से वह इस प्रकार निपटान करने में सक्षम है, इस प्रकार दिए गए अधिकार के अभ्यास से कोई सामान्य महत्व की नैतिक जिम्मेदारी नहीं जुड़ती है। विशाल बहुमत में मानव जाति की प्रवृत्ति और स्नेह उदाहरणों से, लोगों को उन लोगों के लिए प्रावधान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा जो रिश्तेदारी में उनके सबसे करीब हैं और जो जीवन में उनके स्नेह की

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

वस्तु रहे हैं। किसी भी कानून से स्वतंत्र होकर, दुनिया छोड़ने की स्थिति में एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों के बीच वितरित होगा बच्चों या निकटतम रिश्तेदारों के पास वह संपत्ति है जो उसके पास है। कानून द्वारा सुरक्षित किए जाने पर निपटान के अधिकार के प्रयोग में वही उद्देश्य उसे प्रभावित करेंगे। इसलिए मनुष्य के रिश्तेदारों की ओर से एक उचित और अच्छी तरह से अपेक्षित उम्मीद पैदा होती है कि वह जीवित रहेगा। उसकी मृत्यु, उसका प्रभाव अजनबियों को दिए जाने के बजाय उनका हो जाएगा। इस प्रकार बनाई गई अपेक्षाओं को निराश करना और विरासत के संबंध में रिश्तेदारों के दावों की उपेक्षा करना मानव जाति की सामान्य भावनाओं को आघात पहुंचाना है, और नैतिक कानून के दायित्व को मानने में सभी लोगों की सहमति का उल्लंघन करना है। यह नहीं माना जा सकता कि वसीयतनामा स्वभाव की शक्ति देने में उन विचारों की उपेक्षा करके कानून बनाया गया है। दूसरी ओर, यदि वे अकेले खड़े होते, तो संभव है कि वसीयतनामा स्वभाव की शक्ति को रोक दिया गया होता और मालिक की मृत्यु के बाद संपत्ति का वितरण कानून द्वारा समान रूप से विनियमित किया गया होता। लेकिन ऐसे अन्य विचार भी हैं जो पैमाने को वसीयतनामा शक्ति के पक्ष में मोड़ देते हैं।

उनमें से जो किसी व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदारों के रूप में उसके पीछे छोड़े गए भाग्य को साझा करने में सक्षम होंगे, उनमें से कुछ को दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदान किया जा सकता है; कुछ दूसरों की तुलना में अधिक योग्य हो सकते हैं: कुछ को उम्र, लिंग, या शारीरिक दुर्बलता के कारण सहायता की अधिक आवश्यकता हो सकती है। मित्रता और वफ़ादार सेवा के प्रति आजमाए हुए लगाव में ऐसे दावे हो सकते हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। कर्तव्यपरायण और मेधावी आचरण को पुरस्कृत करने की शक्ति में, पैतृक प्राधिकार को एक उपयोगी सहायक मिल जाता है। उम्र सम्मान और ध्यान सुनिश्चित करती है जो इसकी प्रमुख सांत्वनाओं में से एक है। जैसा कि वैन एल्स्ट बनाम हंटर7 में चांसलर केंट ने सच में कहा था 'यह अत्यधिक बुढ़ापे के वफादार परिणामों में से एक है कि यह रुचि जगाना बंद कर देता है, और इसे एकान्त और उपेक्षित छोड़ दिया जाना उचित है'। कानून अभी भी एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति के निपटान पर जो नियंत्रण देता है, वह उन कुशल साधनों में से एक है जो उसे लंबे जीवन में अपनी दुर्बलताओं के कारण ध्यान आकर्षित करने के लिए मिला था। इन कारणों से, मृत्यु की प्रत्याशा में संपत्ति के निपटान की शक्ति को संपत्ति के लिए सबसे मूल्यवान अधिकारों में से एक माना गया है, जबकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अधिग्रहण में उद्योग के लिए एक उपयोगी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। धन और उसके रोजगार में मितव्ययता और मितव्ययिता। इसलिए, प्रत्येक देश के कानून ने संपत्ति के मालिक को अपने पास मौजूद संपत्ति के किसी भी हिस्से को या तो पूरी तरह से या किसी भी स्थिति में वसीयत द्वारा निपटाने का अधिकार दिया है।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

हिंदू कौन है और हिंदू पर्सनल लॉ

हिंदू कौन है?

आज तक 'हिन्दू' शब्द की कोई सटीक परिभाषा न तो किसी क़ानून में और न ही किसी न्यायिक घोषणा में उपलब्ध है; इसने परिभाषा के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया है। हालाँकि, चूँकि हिंदू कानून उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो हिंदू हैं, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि हिंदू कौन हैं, चाहे जो भी परिभाषा संबंधी कठिनाइयाँ हों। यदि प्रश्न को एक अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात, हिंदू कानून किस पर लागू होता है, तो उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों को बताना आसान होगा जिन पर हिंदू कानून लागू होता है। जिन व्यक्तियों पर हिंदू कानून लागू होता है उन्हें निम्नलिखित तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है:

(ए) 'कोई भी व्यक्ति जो धर्म से हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध है, यानी धर्म से हिंदू।

(बी) कोई भी व्यक्ति जो हिंदू माता-पिता से पैदा हुआ है (अर्थात्, जब माता-पिता या माता-पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध हो) यानी जन्म से हिंदू, और

(सी) कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, और जो किसी अन्य कानून द्वारा शासित नहीं है। इस श्रेणी के अंतर्गत दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं:

(i) वे जो मूल रूप से धर्म से हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध हैं, और

(ii) जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं या हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध धर्म में पुनः परिवर्तित हो गए हैं।

हिंदू कानून में वसीयत की उत्पत्ति

वसीयत का विचार शास्त्रों के हिंदू कानून के लिए पूरी तरह से अज्ञात है। 9 हिंदुओं के बीच वसीयत की शक्ति की उत्पत्ति और वृद्धि हमेशा हिंदू वकीलों के लिए एक पहेली रही है। उनके लिए न तो संस्कृत में और न ही स्थानीय भाषाओं में कोई नाम था, केन का कहना है कि संयुक्त परिवार प्रणाली और गोद लेने की प्रथा के कारण, प्राचीन भारत में वसीयतनामा प्रचलन में नहीं आया। धर्म शास्त्रों के इतिहास में 10 केन, पृष्ठ 816, खंड 3, कहता है: ''लेकिन यह मानने की जरूरत नहीं है कि यह विचार अंग्रेजों के आगमन से पहले लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया था। मुसलमानों के बीच वसीयत के बारे में जानकारी थी और उनसे संपर्क करने पर स्वाभाविक रूप से वसीयत का विचार सुझाया जाता था।'' उन्होंने राजतरंगिणी IV के छंद 341-359 का भी उल्लेख किया है, जो 8वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कश्मीर के राजा ललितादित्य के राजनीतिक प्रमाण का प्रतीक प्रतीत होता है। वह कात्यायन के एक पाठ का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह वसीयत की

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

आधुनिक अवधारणा के बहुत करीब है। एक नारो बाबाजी के दिनांक 1775 के एक पत्र का संदर्भ है, जो उनकी बीमारी का जिक्र करने के बाद, उनके अंतिम संस्कार और श्राद्ध के खर्चों के लिए उदार पैमाने पर प्रावधान करता है और अपनी बहू, एक अन्य विधवा के पक्ष में समझौता करता है। , और उसके रिश्तेदारों के बेटों की शादी और उसकी संपत्ति के शेष के वितरण के लिए।

लेकिन ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बाद, लंबे समय तक अभ्यास के माध्यम से इसे स्वीकृत उपयोग के रूप में मान्यता दी गई, और न्यायिक निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा विल द्वारा उपहारों को भारत के सामान्य कानून के भाग और पार्सल के रूप में बाध्यकारी माना गया है। ब्रिटिश भारतीय न्यायालयों के सामने आने वाली सबसे शुरुआती वसीयतों में से एक कुख्यात उमीचंद की थी, जिसकी 1758 ई. में मृत्यु हो गई थी। बंबई के एक मामले में 1789 में बनाई गई एक हिंदू की वसीयत का हवाला दिया गया है। वसीयत द्वारा ऐसे उपहारों का भारत में जीवित लोगों के बीच उपहार और संप्रेषण की प्रथा चली आ रही है। रोमन कानून में भी वसीयतनामा शक्ति कानून उपहार इंटर विवो का विकास प्रतीत होता है। वसीयत द्वारा दिया गया उपहार दाता की मृत्यु पर प्रभावी होता है और यह उसके जीवनकाल में रद्द किया जा सकता है। निरस्त होने तक यह मृत्यु के क्षण तक उपहार का एक निरंतर कार्य है और फिर लाभार्थियों के रूप में नामित व्यक्तियों को निपटान की गई संपत्ति देने के लिए कार्य करता है। वे वसीयतकर्ता की मृत्यु पर संपत्ति लेते हैं, जैसे कि अगर उसने इसे अपने जीवनकाल के दौरान उन्हें दे दिया होता। तो वसीयत का कानून उपहार के कानून द्वारा प्रस्तुत सादृश्य से विकसित हुआ था: भले ही वसीयत को सभी मामलों में मृत्यु पर प्रभावी होने के लिए उपहार के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति और व्यक्तियों के संबंध में समानताएं अच्छी हैं इसे किसको हस्तांतरित किया जा सकता है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925- वैधानिक कानून

• भारतीय वसीयत पर नियंत्रण का दायरा और विस्तार

वर्तमान में हिंदू भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, जैसा कि उस अधिनियम की धारा 111 में उनके द्वारा वसीयतनामा स्वभाव के संबंध में विस्तृत है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान काफी हद तक अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा निर्धारित वसीयत के कानून के सिद्धांत पर आधारित हैं, लेकिन इस देश की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित हैं।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में समेकन क़ानून के प्रावधान न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ऐसे मामलों में अंग्रेजी न्यायालयों के अभ्यास की तुलना में कानून के सिद्धांतों को अधिक विशिष्ट और अधिक निश्चित आधार पर रखना है। उन

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय यह हमारा कर्तव्य है कि हम विशेष रूप से अंग्रेजी मामलों द्वारा बहुत अधिक और क़ानून के शब्दों द्वारा बहुत कम निर्देशित होने से खुद को बचाएं। यह नहीं भूलना चाहिए कि कई मामलों में भारतीय क़ानून इंग्लैंड में अपनाए गए नियमों और सिद्धांतों से हट गया है।34 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 58(2) कहती है कि उसके भाग V के प्रावधान भारत के कानून का गठन करेंगे जो कि लागू होगा। वसीयतनामा उत्तराधिकार के सभी मामले। उक्त धारा की उपधारा (1) उक्त भाग के संचालन से बचाती है-

(1) मुसलमानों के बीच वसीयतनामा उत्तराधिकार।

(2) जनवरी 1866 के पहले दिन से पहले हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन, साथ ही अन्य लोगों द्वारा बनाई गई वसीयतें।

(3) धारा 57 के तहत, यह ध्यान दिया जा सकता है कि हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों के बीच वसीयतनामा उत्तराधिकार को क्रमिक चरणों में वैधानिक नियंत्रण में लाया गया था;

(ए) 1 सितंबर 1879 के बाद बंगाल के उपराज्यपाल के अधीन क्षेत्रों के भीतर और मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के भीतर बनाई गई वसीयत और कोडिसिल;

(बी) उन क्षेत्रों और सीमाओं के बाहर बनाई गई सभी वसीयतें और कोडिसिल, लेकिन उन क्षेत्रों और सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति से संबंधित हैं; और

(सी) जनवरी, 1927 के पहले दिन या उसके बाद की सभी वसीयतें और कोडिसिल और पूर्व वर्गों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

अनिवार्यताएँ

वसीयत की परिभाषा और अनिवार्यताएँ

वसीयत का अर्थ है दाता की मृत्यु के क्षण तक उपहार का एक निरंतर कार्य और यद्यपि उसके जीवनकाल में प्रतिसंहरणीय है, निरसन तक, मृत्यु के क्षण तक उपहार का एक निरंतर कार्य है, और फिर निपटान की गई संपत्ति को देने के लिए कार्य करता है लाभार्थियों के रूप में डिज़ाइन किए गए व्यक्ति। वसीयतनामा एक संस्था या उत्तराधिकारी या निष्पादक की नियुक्ति है जो कानून द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं के अनुसार की जाती है। लैटिन में वसीयत को 'वोलंटस' कहा जाता है जिसका उपयोग वसीयतकर्ता के इरादे को व्यक्त करने के लिए रोमन कानून के ग्रंथों में किया जाता है। विलियम, वसीयत और निर्वसीयत उत्तराधिकार के अनुसार, वसीयत मूल रूप से एक अमूर्त दायित्व थी जिसे एक दस्तावेज़ में निर्दिष्ट किया गया था। 'वसीयतनामा' शब्द 'वसीयतनामा' से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह मन के दृढ़ संकल्प की गवाही देता है। ULPAIN ने वसीयत को इस प्रकार परिभाषित किया है, "वसीयतनामा इस्ट मेंटिस

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

नोस्ट्रेजस्टा कॉन्टेस्टियो इन आईडी सोलेमनिटर फैक्टा टू पोस्ट मार्टम नोस्ट्रम वैलेट"। मोडास्टिनस ने इसे लैटिन शब्द 'वॉलंटस' के आधार पर "वॉलंटैटिस नोस्ट्रे जस्ट सेंटेंशियल डे को क्वॉड क्विस पोस्टमॉर्टम सुम फिएरी वेलिट" के रूप में परिभाषित किया है। जरमन के अनुसार, वसीयत एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का निपटान अपनी मृत्यु के बाद प्रभावी बनाता है और जो अपने स्वभाव से चलनशील और उसके जीवन के दौरान रद्द करने योग्य होता है। (नाम ओमने टेस्टामेंटम मोर्टे कंसुमेटुमेस्ट; एट वॉलुंटे टेस्टामेंटोरिक इस्ट एंबुलेटरिया यूएसक्यू ओड मॉर्टम)। इस प्रकार प्रत्येक वसीयत मृत्यु द्वारा समाप्त हो जाती है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वसीयतकर्ता की वसीयत चलन में रहती है। लॉर्ड पेनज़ेंस ने कहा है कि "वसीयत मनुष्य के वसीयतनामा के इरादों का समुच्चय है, जहां तक वे लिखित रूप में प्रकट होते हैं, क़ानून के अनुसार विधिवत निष्पादित होते हैं"। टैगोर बनाम टैगोर मामले में, न्यायिक समिति के आधिपत्य ने इस प्रकार कहा, इसका अर्थ है मृत्यु के क्षण तक उपहार का एक निरंतर कार्य। संपत्ति का ऐसा निपटान, दाता की मृत्यु पर प्रभावी होता है, हालांकि उसके जीवनकाल में रद्द किया जा सकता है, रद्द होने तक, मृत्यु के क्षण तक उपहार का एक निरंतर कार्य होता है और फिर लाभार्थियों के रूप में नामित व्यक्तियों को उचित रूप से निपटान करने के लिए कार्य करता है ।"

स्विन बर्न बताते हैं कि "एक वसीयतनामा एक व्यक्ति के दिमाग या उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ण और पूर्ण घोषणा है जिसे उसने अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के निपटान के माध्यम से करने के बारे में सोचा होगा। वसीयत भी दस्तावेज रही है, जिसका अर्थ है, "प्रत्येक लेख संपत्ति का स्वैच्छिक मरणोपरांत वितरण करता है"। किसी क़ानून के अभाव में, वसीयत मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के हिंदुओं पर लागू होने से पहले, हिंदुओं की मौखिक वसीयत को वैध माना जाता था। एक मौखिक वसीयत भी निहित हो सकती है; यदि लिखित रूप में इसे हस्ताक्षरित या प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।79 लेकिन वसीयत के रूप में कार्य करने के लिए, लेखन पूर्ण और क्रियाशील होना चाहिए। किसी दस्तावेज़ को वसीयत तभी कहा जा सकता है जब इसे मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को विनियमित करने के इरादे से निष्पादित किया जाता है "वरस पत्र" या नामांकन को वसीयत के रूप में नहीं माना जा सकता है।80 वैधानिक आवश्यकताओं के अभाव में, लिखित दस्तावेजों को संचालित करने के लिए रखा गया है वसीयत के रूप में, किसी भी रूप में या किसी भी नाम से वे अस्तित्व में आए हों। अधिकारियों को संबोधित याचिकाएं, कार्य या गोद लेने, जमा के लिए आवेदनों में घोषणाएं या एक पत्र में किए गए विवरण को वसीयत के रूप में संचालित माना गया है, बशर्ते कि उनके पास वसीयत हो। वसीयत की अन्य विशेषताएँ। हालाँकि, जहाँ एक पक्ष वैध वसीयत के

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

लिए उचित सत्यापन की आवश्यकता वाले क़ानून द्वारा शासित होता है, वहाँ अधिकारियों को संबोधित एक मात्र पत्र होता है जिसमें मृतक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाती है कि बिना किसी समस्या के उसकी मृत्यु पर, उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होगी संपत्ति के मालिक, सत्यापन के अभाव में मान्य नहीं होंगे।

(i) वसीयत की वैधानिक परिभाषा धारा 2(एच), भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, वसीयत को "उसकी संपत्ति के संबंध में वसीयतकर्ता के इरादे की कानूनी घोषणा, जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद लागू करना चाहता है" के रूप में परिभाषित करता है। . यह परिभाषा ब्लैकस्टोन और अन्य का अनुसरण करती है। वसीयत किसी व्यक्ति के इरादे की कानूनी घोषणा है, जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद निष्पादित करना चाहता है, या एक साधन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद प्रभावी होने के लिए अपनी संपत्ति का निपटान करता है।

(ii) वसीयत की अनिवार्यताएं वसीयत के लिए तीन अनिवार्यताएं हैं:-

(ए) यह वसीयतकर्ता, यानी वसीयत करने वाले व्यक्ति के इरादे की कानूनी घोषणा होनी चाहिए। कानून अनुपालन हेतु फॉर्म और औपचारिकताएं निर्धारित करता है। जब तक उन औपचारिकताओं का पालन नहीं किया जाता, कोई कानूनी घोषणा नहीं हो सकती। दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर होना चाहिए; इसे कानून द्वारा आवश्यक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए। एक विशेषाधिकार रहित वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए।

(बी) इरादे की घोषणा वसीयतकर्ता की संपत्ति के संबंध में होनी चाहिए। किसी मृतक द्वारा अपनी पत्नी को गोद लेने का दिया गया अधिकार, जिसका उपयोग उसकी मृत्यु के बाद वह करेगी, कोई वसीयत नहीं है। इसी तरह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद नाबालिग बेटे के लिए अभिभावक नियुक्त करने वाला दस्तावेज़ भी। 83 दस्तावेज़ के अंतर्गत संपत्ति का निपटान होना चाहिए। जहां एक हिंदू वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत नामक दस्तावेज़ केवल उसकी पत्नी को गोद लेने का अधिकार देता है, उसे अपनी संपत्तियों में कुछ भी दिए बिना, वसीयत का चरित्र स्थापित नहीं होता है। संपत्ति का निपटान होना चाहिए।84 जहां संपत्ति का कोई निपटान नहीं है, बल्कि केवल उत्तराधिकारी (महंत के रूप में) की नियुक्ति है, यह वसीयत नहीं है।85 हिंदू संपत्ति निपटान अधिनियम, 1916 के तहत, हस्तांतरण पर रोक है हालांकि, अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में इस शर्त को हटा दिया गया है कि अंतर-जीवित स्थानांतरण द्वारा स्वभाव संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के अध्याय II के प्रावधानों से बंधा होगा और वसीयत द्वारा निपटान प्रावधानों के अधीन होगा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925.86 की धारा 113,

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

114, 115 और 116 सरकार शास्त्री अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति से निपटने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता को उचित ठहराने में असमर्थ हैं। वह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वसीयत की परिभाषा की आलोचना करते हैं क्योंकि यह "परस्पर निर्भरता के भ्रम" के तार्किक दोष से दूषित है।

(सी) दस्तावेज़ में यह इच्छा व्यक्त की जानी चाहिए कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इरादे को लागू किया जाना चाहिए। वसीयतकर्ता का इरादा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए ताकि "उसी को कार्यान्वित किया जा सके।" वसीयत के स्पष्ट शब्द होने चाहिए। हालाँकि, ऐसा हो सकता है कि एक वसीयतकर्ता अनजाने में उपहार देने के अपने इरादे को व्यक्त करने से चूक जाता है, लेकिन ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो दिखाते हैं कि वसीयतकर्ता इस धारणा के तहत है कि उसने एक इरादे के साक्ष्य के रूप में एक स्वभाव बनाया है, ऐसे मामलों में, यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि वसीयतकर्ता के इरादे को पूरा करने में गलती हुई है, यदि वसीयत के अन्य प्रावधान ऐसा करने की अनुमति देंगे तो न्यायालय ऐसे इरादे को प्रभावी कर सकता है89 एक मामले में मृतक ने लिखा, "मेरे निधन पर मेरे कानून के अनुसार पत्नी मेरी संपूर्ण चल संपत्ति की पूर्ण (पूर्ण) मालिक बन जाएगी, परिणामस्वरूप उसके संबंध में किसी वसीयत की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवरण का उल्लेख करते हुए हॉरविल, जे. ने कहा,90 "इससे अधिक स्पष्ट संकेत की कल्पना करना मुश्किल है कि मृतक ने दस्तावेज़ के तहत अपनी चल-अचल संपत्ति वसीयत नहीं की थी।91 यह माना गया है कि यह दिखाने के लिए मौखिक साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है विलेख के निर्माता की मृत्यु के बाद ही स्वभाव को संचालित करने का इरादा था।

निष्कर्ष

पिछले वर्षों में भारतीय संदर्भ में विभिन्न धर्मों में प्रचलित वसीयती उत्तराधिकार के संबंध में व्यापक अध्ययन और शोध किया गया है। वसीयती उत्तराधिकार की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न धर्मों, वैधानिक कानूनों और प्रथागत कानूनों पर जोर दिया गया है। तो अब वसीयती उत्तराधिकार की अवधारणा, कार्यान्वयन और प्रक्रिया को समझने के लिए एक संक्षिप्त निष्कर्ष दिया जा रहा है। भारत में उत्तराधिकार को पहले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 द्वारा विनियमित किया गया था। यह अधिनियम मुख्य रूप से अंग्रेजी कानूनों पर आधारित था, और कुछ अपवादों के अधीन, ब्रिटिश भारत में लागू कानून का गठन किया गया था, जो वसीयतनामा और निर्वसीयत उत्तराधिकार के सभी वर्गों पर लागू था। हालाँकि, अपवाद इतने व्यापक थे कि भारत के सभी मूल निवासियों को इसके अंतर्गत बाहर रखा गया था। अतः, 1870 में, हिंदू विल्स अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के कुछ भाग हिंदुओं द्वारा बनाई गई सभी वसीयतों और कोडिसिलों पर भी लागू होंगे। बाद में 1881 में प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

पारित किया गया और इस एक्ट को हिंदू और मुस्लिम दोनों पर लागू किया गया। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, 1865 के पहले अधिनियम, हिंदू वसीयत अधिनियम, प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम और पारसी निर्वसीयत उत्तराधिकार अधिनियम को समेकित करता है। अधिनियम की प्रस्तावना इंगित करती है कि अधिनियम का उद्देश्य निर्वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार पर लागू कानून को समेकित करना है। यह काफी हद तक अंग्रेजी कानून के नियम का प्रतीक है। जहां तक उन मामलों का संबंध है जो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, हिंदू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होते हैं और मुस्लिम अपने व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अग्रवाल, के.बी., फैमिली लॉ इन इंडिया, क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, नीदरलैंड्स, 2010।

एग्नेस, फ्लाविया, पारिवारिक कानून: विवाह, तलाक, और वैवाहिक मुकदमेबाजी, वॉल्यूम। II, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011।

आइंस्ली टी. एम्ब्री; (एड), इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एशियन हिस्ट्री वॉल्यूम 2, कोलर मैकमिलन पब्लिशर्स, लंदन, 1988।

अय्यर. के.सैंड एल.त्रिपाठी दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और संबद्ध एवं संज्ञेय अपराध मल्होत्रा लॉ हाउस, इलाहाबाद, 1996।

अख्तर, नसीम, तलाक और न्यायिक पृथक्करण पर पारिवारिक कानून, दीप और दीप प्रकाशन प्राइवेट। लिमिटेड, नई दिल्ली, 2003।

एरीन, जूडिथ, पारिवारिक कानून पर मामले और सामग्री, तीसरा संस्करण, फाउंडेशन प्रेस, वेस्टबरी, 1992।

बंसल, अश्विनी कुमार, आर्बिट्रेशन और एडीआर, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी, दिल्ली, 2007।

बार्टन, क्रिस और गिलियन डगलस, लॉ एंड पेरेंटहुड, बटर वर्थ्स, लंदन, 1995।

बसु, एम, हिंदू महिला और विवाह कानून, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2001।

बत्रा, मंगुला, भारत में बच्चों से संबंधित महिलाएं और कानून, इलाहाबाद लॉ एजेंसी, फ़रीदाबाद, 2001।

बेरी, बी.पी., दहेज निषेध अधिनियम 1961, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 1990।

बेरी, बी.पी., भारत में विवाह और तलाक का कानून, दूसरा संस्करण, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ 1989।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

भट्टाचार्य, संजय, सीगल, विलियम, फैमिली लॉ: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, वॉल्यूम। V-VI: हस्तक्षेप और प्रबंधन, डीप एंड डीप प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008।